(iii) Reported shortage of Coal in Punjab

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA (Faridkot) : Sir, with your kind permission, I would like to raise a matter of very urgent public importance. The coal shortage in Punjab is so grave that several industries in the State have already closed down and others have reduced their production causing distress among workers and employees. The production of electricity has gone down by 35 per cent to 50 per cent in Gurunanak Thermal Plant, Bhatinda, due to uncertain and defective supply of coal.

The brick kilns are facing closure and they could supply only 3 crores of bricks against the target of 80 crores to the State Government for the construction of link roads, grain markets, schools, hospitals, focal points lining of canals and water courses as the sponsored coal quota was virtually out of stock. According to Daily Tribune dt. 15-4-79, there are complaints that the good quality of coal whose price is Rs. 5000/- per wagon is being sold at Rs. 17000 in blackmarket. The price of bricks has risen upto Rs. 250/- to Rs. 260/- per thousand against the control price of Rs. 140/-.

The private building activity is almost stopped. Under such a serious situation, will the Minister of Energy take immediate steps to help the State and assure full supply of coal to Punjab at the earliest.

(iv) Financial assistance for rehabilitation of agricultural and landless labourers in Morena and Gwalior divisions of Madhya Pradesh.

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय की ओर श्रम मंत्री जी तथा इस पवित्र सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के चंबल संभाग मुरैना व ग्वालियर संभाग के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना जिलो मे करीब डेढ़ लाख लोग जो खेतिहर मजदूर व भूमिहीन बंधक श्रमिक है बेघरबार हैं. जिन्हें बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इन बेघरबार बंधक लोगो को बसा सके। अत: मैं केन्द्र सरकार व श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करता हू कि इन बेघरबार लोगों को बसानेहेतु मदद दी जाये। बहुत से बेघरबार लोग बगलादेश से आये हुए शरणार्थी है, जिन्हें तुरन्त बसाया जाना आवश्यक है। उनमें से अधिकाश लोग अनुसूचित जाति तथा तथा जनजाति के है।

भिंड-मुरेना मे कई लाख एकड़ भूमि बीहड़ की है। हर साल बरसात में खेतिहर भूमि कटती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इस भूमि को समतल कराके भूमिहीनों मे बांट सकें। इसलिए यह आवश्यक है कि फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत मुरेना व ग्वालियर संभाग की भूमि का कटाव रोका जाये और इस भूमि का समतलीकरण 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत कराया जावे। इस भूमि पर बेघरबार लोगों को बसा कर उन्हे आर्थिक मदद दी जाये। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, शरणार्थियों और बेघरबार लोगों को निशुल्क भूमि दी जाए।

अगर यह कार्य नहीं किया गया, तो श्रमिकों और बेघरबार लोगो मे कभी भी भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए शासन से मेरी यह मांग है कि भिंड, मुरेना, ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया जिलों के बेघरबार भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से बसाया जाये। रोजगार के अभाव मे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। अत: मैं शासन से मांग करता हूं कि बगला देश से आये हुए शरणार्थियो, सिंधी भाइयो, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बंधक बेघरबार लोगो को तुरन्त बसाने की कार्यवाही की जाये। बंधक मजदूरों को मुक्ति दिला कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जायें।